खंड-'अ'

प्रश्न 1. इस प्रश्न में 15 अतिलघुत्तरीय उप प्रश्न हैं. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं । प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंकों का है।

3x15=45

Question.1 This question contains 15 very short type subquestions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsury. Each question carries 03 (Three Marks)

प्रश्न: PRADEEP Saraswariya,

उत्तर : Number- 7987647889

Paper-2 (प)

Date [27/11/22]

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर : (1) संविधान दिवस 26 नवम्बर को बनाया जाता है
26 नवम्बर 1949 को संविधान तैयार हो गया था
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर : (B) (I) 1973 में पहल मिलप आया।
(II) संविधान मूल संरचना की उत्पत्ती हुई
(III) संसद संविधान संशोधन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगे।

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर : (C) (I) संविधान भाग (4) अनुच्छेद (36-51) तक
(II) आयरलैण्ड संविधान से प्रेरित
(III) गैर न्यायपोषित [सामाजिक लोकतंत्र द्योतक]

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर : (d) (I) 51(A) संविधान भाग 4(A) मौलिक कर्तव्य
को भाग 42वा संशोधन (1976) को जोड़ा गया
स्वर्णसिंह समिति अनुशंसा पर [संख्या 11]

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (e) (1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा मिला (2018) अनुच्छेद 338(B) व 342(A) जोड़े गए।

प्रश्न:

उत्तर: (f) न्यायपालिका अपने निर्णय को लागू करने या पूर्ण न्याय प्रदान हेतु डिक्री-आदेश जारी कर सकती है उदा (BMW) गाड़ियों का निर्णय

प्रश्न:

उत्तर: (ज) कोई भी व्यक्ति या संगठन अन्य वर्ग-समूह को न्याय दिलाने के लिए (PIL) द्वारा न्यायालय तक जा सकता है

प्रश्न:

उत्तर: (H) सुशील चन्द्रा वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2021 में नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है

प्रश्न:

उत्तर: (I) यह दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है।

compulsury. Each question carries 03 (Three Marks)

प्रश्न:

उत्तर: (J) (1) अनुबंध (OB) द्वारा गठित | संरचना | अध्यक्ष शासनकाल द्वारा निर्धारित अन्य सदस्य कार्य - शासन भर्ती परीक्षा आयोजन करती

प्रश्न:

उत्तर: (K) समुदाय विशेष के हितो की पूर्ति हेतु बने संगठन जिनका उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्ती हो (CBO) कहलाता है

प्रश्न:

उत्तर: (L) जय प्रकाश नारायण को लोकनायक कहते है वे समाजवादी नेता रहे उनकी रचनाएं समाजवाद क्यों, समाजवाद से सर्वोदय आदि है

प्रश्न:

उत्तर: (M)

प्रश्न:

उत्तर: (N) सरकार की नीतियो का मूल्यांकन करने तथा उन्हे उत्तरदायी बनाने वाली विभिन्न संगठनात्मक इकाईयां उदा - NGO, CBO, ट्रस्ट आदि

प्रश्न:

उत्तर : (c) सोशल मिडिया जैसे ट्विटर पर अपनी अभिव्यक्ति करना माइक्रोब्लॉगिंग कहा जाता है।

प्रश्न:

PART-B

uestion 2 Write the answers of any ten of the following questions in maximum 50 words

प्रश्न: (2.2) पू./M =

उत्तर: (A) यह लेखा परीक्षक (148) अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
इसकी निम्न भूमिका है।
(i) सरकार वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना
(ii) सार्वजनिक वार्षिक व्यय-आय की लेखा परीक्षा करना।
(iii) कुल प्राप्तियों व व्यय, तथा अनुदान आदि की जाँच पर कार्यवाही राज्यों के लिए करता है।
(iv) लोकलेखा समिति को सहायता प्रदान करता है
(v) लोकवित्त में पारदर्शिता उत्पन्न करता है।
(vi) भ्रष्टाचार नियंत्रण, अनुशासनपूर्ण वित्त व्यवस्था आदि

प्रश्न: (2.2) पू./M =

उत्तर: (B) NALSA अधिनियम 1987 के तहत (NALSA) एक वैधानिक निकाय है।
उद्देश्य → (i) सुगम-सुलभ न्याय तक पहुँच बढ़ाना
(ii) न्याय की लागत कम करना।
कार्य → (i) निशुल्क विधिक सेवा अनुच्छेद 39(A) तहत प्रदान करता है।
(ii) वंचित वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान करना
(iii) वंचित व गरीब वर्ग को वकील प्रदान करना।
(iv) न्यायपालिका में मामला दर्ज करने में सहायता
(v) जिला अदालतों का आयोजन करना
(vi) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश देना।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(c) विधि व कानून के प्रतिपालन हेतु नागरिक सहभागिता आवश्यक। निम्न प्रकार नागरिक निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं

(i) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मतदान, रेफ्रिरेंडम। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकप्रतिनिधि चुन कर

(ii) समाचारपत्रों, मिडिया, में अपने विचार रखकर

(iii) संबंधित बिलों के सार्वजनिकरण तथा उस पर सुझाव देकर।

(iv) पंचायती स्तर पर ग्रामसभाओं के द्वारा।

(vi) एक विषय पर शहर में लोगों से जनमत संग्रह

(v) संघठन, ट्रस्ट, सिविल सोसायटी के रूप में शपथपूर्वक।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(d) निम्न प्रकारों से बदल सकता है।

(a) सकारात्मक कार्य की प्रशंसा कर उस धारणा को प्रोत्साहित करना उदाहरण बच्चे-दो-ही-अच्छे

(b) कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक कर उसके समाप्त करने में उदाहरण घर की बेटी, बेटी-बचाओ-बेटी...

(c) भ्रष्टाचार का खुलासा कर तथा उसके कठोर दंड प्रदर्शन कर नकारात्मक मनोवृत्ति उत्पन्न करना।

(d) सरकारों के कार्य की वार्षिक समीक्षा कर सब समाज में उत्तरदायित्व उत्पन्न कर सकते हैं

(e) समानता, बंधुत्व, सहिष्णुता भावना का प्रचार। उदाहरण हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई हम सारे भाई है

प्रश्न: (2.2) पू./M = 0

उत्तर :

(E) अंत्योदय दीनदयाल द्वारा प्रतिपादित विचार है जिसके अनुसार संसाधनों का वितरण समाज के अंतिम वर्ग तक होना चाहिए इस हेतु आवश्यक है – (i) सत्ता विकेन्द्रीकरण (ii) रोजगार अधिकार (iii) लघु-कुटीर उद्योग प्रोत्साहन (iv) संपत्ति सुरक्षा (v) कृषि विकास पर ध्यान दिया जाए।

प्रभाव → सामाजिक रोजगार सृजन
प्रभाव → आर्थिक समानता को बल मिलेगा
प्रभाव → उत्पादकता को बढ़ावा
प्रभाव → सामाजिक न्याय प्राप्ति

प्रश्न: (2.2) पू./M = 0

उत्तर (F) मैक्स वेबर अनुसार शक्ति आरोपण की अभिव्यक्ति है जो बाध्यकारी रूप में होती है वेबर ने इसके प्रकार बताए

(i) वैधानिक शक्ति → पद की उत्तरदायित्व पूर्ति हेतु प्राप्त उदा. IAS, IPS,

(ii) संविदा शक्ति → योग्यता व कुशलता के कारण प्राप्त।

(iii) करिश्माई शक्ति → पवित्रता व विश्वसनीयता के कारण उत्पन्न (उदा. गांधी, हिटलर)

(iv) पारितोषिक → कोई सुविधा, वेतन प्रदान करने के कारण प्राप्त उदा. कंपनी के मालिक की शक्ति

(v) उत्पीड़क → किसी वस्तु, सेवा, से वंचित करने के कारण उत्पन्न उदा. पुलिस, न्यायपालिका

निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 (छः) अंकों का है।

Question 2 Write the answers of any ten of the following questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

प्रश्न: (2.2)

उत्तर:

(अ) 74 वाँ संशोधन 1992 में नगर निकायों के संवैधानिक स्थापना के लिए किया गया।

प्रावधान → (i) भाग 9(A) अनुच्छेद (243 P – 243 ZG)

(ii) अनुसूची 12 (विषय 18) जोड़े गए।

(iii) त्रिस्तरीय नगरीय निकाय संरचना नगरनिगम / नगरपालिका, नगरपंचायत।

(iv) जिला (243ZD) महानगर (243ZE) नियोजन समिति स्थापना।

प्रभाव
→ शहरों के लिए रचना हेतु संवैधानिक ढांचा
→ सत्ता का विकेंद्रीकरण
↓ शहरों का बेहतर प्रबंधन हुआ
← जनभागीदारी को प्रोत्साहन

प्रश्न: (2.2)

उत्तर (4) राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय दल घोषित (ECI) द्वारा
(i) BJP (ii) BSP (iii) कांग्रेस (iv) राष्ट्रीय कांग्रेस (v) तृणमूल कांग्रेस (vi) CPI (vii) CPI (मार्क्सवादी)
आवश्यकताएँ – (i) लोकसभा या विधान सभा चुनावों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो।
(ii) लोकसभा चुनाव में 2% सीटें चार भिन्न-2 राज्यों से जीती हों।
(iii) तीन या तीन से अधिक राज्यों में राज्य स्तर दल घोषित किया गया हो।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर (I) भिन्न प्रकार प्रयोगिता बनी हुई है।
(a) इसकी अब तक पहुंच डिजिटल डिवाइस से प्रभावित नहीं होता है।
(B) अधिक विश्वसनीय क्योंकि परम्परागत व लोगों के लिए अनुकूल
(c) बढ़ते फेक न्यूज, कार्पोरेट न्यूज चैनल हस्तक्षेप, 24×7 मिडिया चैनल आदि के कारण प्रिंट मिडिया लोगों के बीच अधिक विश्वनीय व भरोसेमंद है।
(d) विस्तृत व सत्य सूचनाएँ प्रदान करने में अधिक सहायक।
(e) वस्तुपरक विचार में स्वीकार्यता अधिक।

SECTION -A

खंड-'अ'

प्रश्न: 2. निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 (छ:) अंकों का है। 5x10=

Question.2 Write the answers of any ten of the following questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

प्रश्न: (2.2) पू./M =

प्राप्त

उत्तर : (i) लोकप्रशासन के क्रियाही सिद्धान्त के प्रतिपादन में हेनरी फियोल, लिंडाल उर्विक, लूथर गुलिक प्रमुख योगदान हो।

प्रमुख सिद्धान्त → (i) श्रम विभाजन → प्रत्येक श्रमिक, प्रबंधक, कार्य विभाजित हो

(ii) पदसोपान की व्यवस्था (iii) सत्ता के प्रत्यायोजन की व्यवस्था (iv) स्थायी नियुक्ति (v) निश्चित वेतन (vi) क्रमबद्धता होनी चाहिए (vii) अधिकतम समन्वय (viii) संगठन के प्रति समर्पण (ix) समितियां व समन्वय (x) उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो (xi) केन्द्रीयकरण। आदि।

प्रश्न: (2.2) पू./M =

(A) संघवाद वह अवधारणा है जिसमें कुछ राज्य मिलकर एक केन्द्र का निर्माण करते है तथा उनके मध्य क्षैतिज व उदग्रधिर संबध होते है।

संघवाद भारतीय संविधान की मूलसंरचना का भाग है कई संवैधानिक उपबंध व विशेषता इसकी पुष्टि करते है।

(I) भारत का लिखित संविधान।
(II) स्वतंत्र न्यायापालिका (124) Art
(III) द्विस्तरीय सरकार (केन्द्र-राज्य)
(IV) शक्तियो का विभाजन (सातवी सूची)
(V) संविधान कठोर (368) तक
(VI) द्विसदन प्रणाली (राजभागीदारी - राज्यसंभा)

परन्तु के.सी. व्हियर ने इसे अर्द्धसंघिय कहा है इसके निम्न कारण।

(I) एकल संविधान की उपस्थिति।
(II) एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना
(III) एकल नागरिकता का प्रावधान।
(IV) राष्ट्रीय आपात काल व राष्ट्रपति शासन
(V) अखिल भारतीय लोक सेवा।

Nema Books

(5) राज्यपाल की नियुक्ति शक्ति (केन्द्र) द्वारा।

(6) संघ सूची में अधिक महत्वपूर्ण विषय, अवशिष्ट शक्ति केन्द्र में निहित होना।

(7) संसद को ही संविधान संशोधन शक्ति प्राप्त। तथा समवर्ती सूची में प्राथमिकता।

(8) राज्यों को विभाजित करने, नाम परिवर्तन एवं विस्तार आदि अधिकार संसद को [A-3]

(9) अनुच्छेद (249), (253) तहत संसद द्वारा राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण शक्ति आदि

उपरोक्त कारक संविधान की केन्द्रीय मूलों की प्रकृति को स्पष्ट करते है इसलिए भारतीय संविधान प्रकृति पूर्ण संघीय न होकर अर्द्ध संघीय है।

परन्तु निम्न उपायों द्वारा संघात्मकता को बल दिया गया है जो अंतर्राज्यीय परिषद, जल परिषद, क्षेत्रीय विकास परिषद या आंचलिक परिषद आदि द्वारा एवं पंचायतीराज स्थापना की है सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया इस तरह भारतीय संघ अपनी प्रकृति में अनूठा है जो स्थिति अनुकूल है

Nema Books -9200333367

...made explicitly before the answer. Each

पू./M =

(B) न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य है। संसद या राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों व कानूनों की समीक्षा करना की वे संविधान व मूल अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं यदि हो तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है।

संविधान के निम्न अनुच्छेदों के तहत न्यायपालिका को पुनःविलोकन शक्ति प्राप्त है।

(i) मौलिक अधिकार (Art-13-35)
(ii) स्वतंत्र न्यायपालिका (124/214)
(iii) शक्ति पृथक्करण अवधारणा।
(iv) नीति निर्देशक तत्व (Art-37)
(v) संघात्मक व्यवस्था के तहत
(vi) कल्याणकारी राज्य अवधारणा तथा प्रस्तावना (सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय)
(v) विभिन्न न्यायिक निर्णय (मिनर्वा मिल्स)

• संसद द्वारा निम्न प्रकारों से न्यायिक पुनर्विलोकन पर प्रतिबंध लगाने के उपाय किए हैं

(I) प्रथम संविधान संशोधन [~~प्रथम~~ नवी अनुसूची] न्यायीक समीक्षा बाहर रखेगी।

(II) २४ वे संशोधन द्वारा असीमित संशोधन शक्ति संसद ने प्राप्त की।

(III) २५ वे संशोधन द्वारा संशोधन समीक्षा शक्ति समाप्त की गयी।

(IV) ४२ वे संशोधन द्वारा भी कम किया गया। [Art 31(B), 31(C)] द्वारा

न्यायीक पुनरावलोकन के संबंध में न्यायपालिका निर्णय :- (I) केशवानंद भारती वाद 1973 में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया।

(II) मिनर्वा मिल्स 1980 वाद में इसे मूल संरचना भाग घोषित किया।

(III) I.R. कोएल्हो वाद 2007 में ~~स~~ नवी अनुसूची विषय इसके अंतर्गत लाए गए

| महत्व | → (I) राजनैतिक निरंकुशता पर नियंत्रण

(II) संविधान की सुरक्षा।

(III) मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।

(IV) ~~स~~ कार्यपालिका-विधायिका की शक्ति सीमा निर्धारण व पहल आदि।

न्यायीक समीक्षा बेहतर लोकतांत्रिक सरकार स्थापना का आधारभूत स्तंभ है।

(c) भारतीय स्वतंत्रता को वर्तमान में (75) वर्ष हो रहे है परन्तु संविधान वादियो ने जिस आधुनिक लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था वह अभी तक पूर्ण नही हो।

भारतीय लोकतंत्र अभी भी पूर्ण परिपक्व नही हो सका। भारतीय राजनिति के आज महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, व तकनीकी विकास ना होकर धर्म, जाति की विषय महत्वपूर्ण बने हुए है। इसलिए भारतीय राजनीतिक दलो द्वारा राजनीतिक विषय हेतु इनका प्रयोग किया जाता है

जिनके निम्न उदाहरण देखने को मिलते है

(1) धर्म → भारतीय राजनिति का यह महत्वपूर्ण मुददा जो धार्मिक ध्रुविकरण को उत्पन्न करता है जहा धर्म विशेष के प्रति सद्भावना अन्य के प्रति नफरत उत्पन्न की जाती है। तथा

धर्म के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। U.P चुनाव 2022 में ए.यु.प ने (50) मुस्लिम बहुल इलाको से मुस्लिम प्रतिनिधि उतारे गए।

(13) जाति → भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जाति भारतीय पहचान की मुख्य इकाई जिसके इसके नाम पर संगठन बनाए जाते है तथा वोटिंग की जाती है

उदा० बिहार, उतरप्रदेश दलित, पिछडो की राजनीति

(14) वर्ग → वर्ग विशेष का ध्रुवीकरण भारतीय राजनीतिक विशेषता है जैसे अल्पसंख्यक का ध्रुवीकरण, महिलावर्ग को लुभाना तथा आरक्षण की राजनीति। इस

अपरिपक्वता का निवारण पर्याप्त शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कठोर चुनाव संहिता जनजागरूकता तथा राजनैतिक जैसे उपायों से किया जा सकता है।

Nema Books -9200333367

(i) सरकार के निर्णयों में जन भागीदारी व उनके नीतियों के उत्तरदायित्व निर्धारण में सिविल सोसायटी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं सिविल ~~सोसाइट~~ सोसायटी के रूप में म.ज.स. व स्वयं सहायता समूह सरकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(i) नागरिक मांगों को सरकार के सम्मुख पेश करना या मांगों को उठाना उदा. गुजरात में भारत (RTI) मांग आंदोलन या (2005) RTI (Act) पारित करने में सफल रहा।

(ii) यह सरकार व लोगों के मध्य विचार-विमर्श के सेतु के रूप में कार्य करते हैं।
उदा. म.ज.स. की मांग द्वारा ही 1984 परिवार न्यायालय स्थापित हुई।

(iii) यह विभिन्न नीतियों की समीक्षा उजागर कर कमीयों को उजागर करते है हाल ही में (NMP) 2020 की कमीयों को उजागर किया गया।

(iv) वंचित वर्ग की मांगों को सरकार तक पहुंचाना तथा उनके हित में नीतीयां बनाना उदा. मनरेगा।

(v) प्रशासन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता की प्रेरणा सरकार को प्रदान करना।

(vi) आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव प्रदान करना उदा. ASSER रिपोर्ट (प्रथम N.G.O)।

सीमाएं - (i) N.G.O का राजनीतिकरण।

(ii) स्वयं सहायता समूहों में आत्मनिर्भरता।

(iii) FCRA 2020 कानून।

(iv) मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में N.G.O से लगाव।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा (स्वयं सहायता समूह)।

यह सिविल सोसायटी के वह भाग जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सरकारी नीतीयों के निर्माण में सहयोगी होते है।

(E) राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत केन्द्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य स्तर राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया गया।

(ब) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग → अधिनियम

धारा-3 के तहत इसका गठन किया गया।

→ कुल → 6 सदस्य

संरचना → (1) अध्यक्ष → पूर्व SC मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश।

(2) न्यायिक सदस्य → (i) SC पूर्व न्यायाधीश
(ii) HC पूर्व न्यायाधीश

(3) अन्य सदस्य → मानवाधिकार विशेषज्ञ
→ एक महिला सदस्य अनिवार्य

(4) 7 पदेन सदस्य → SC आयोग, ST आयोग OBC आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, दिव्यांगजन के लिए विशेष आयुक्त, बाल संरक्षण आयुक्त।

कार्य → (i) मानवाधिकार उल्लंघन पर जाँच करना
(ii) स्वयं संज्ञान या शिकायत प्राप्ती पर कार्यवाही करना।
(iii) पिड़ित को क्षतिपूर्ती दिलवाने की सिफारिश करना।
(iv) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाओं को लागु करवाना।
(v) न्यायालय में मानवाधिकार मामलों में पेश होना।
(vi) राज्य पुलिस स्टेशनों, जेल, सुधारगृहों की जाँच।

(2) राज्य मानवाधिकार आयोग :- धारा-21 द्वारा बनाया गया।

(a) स्थापना → कुल 3 सदस्य।
(i) → 1 अध्यक्ष → HC पूर्व मुख्य न्यायाधीश
(ii) → 1 सदस्य → HC अधिवक्ता
(iii) → 1 सदस्य → मानवाधिकार विशेषज्ञ

'मध्यप्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापना हुई के तहत 1995 में की गयी।

कार्य → (i) राज्य स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन मामले की जाँच करना।

अत: यह दोनों आयोग भारत में मानवाधिकार सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

कहा गया है।

PART-B

(A) (I) प्रस्तावना संविधान का भाग है परन्तु यह ना तो विधायिका शक्ति का स्रोत है ना ही उनकी शक्ति पर प्रतिबंध (केशवानन्द भारती वाद)

(B) (I) संघीय लोकसेवा आयोग से संबंधित Article
(II) राष्ट्रपति द्वारा आयोग स्थापना होगी
(IV) सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।

(C) (I) धर्म/जाति/वर्ग (II) एंटीमकंपनीबेरी
(III) उपविकल्प (नेतृत्व) (IV) सरकारी कार्य

(D) (I) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित
(II) उद्देश्य → उपभोक्ता विवाद का समाधान
धारा-17 द्वारा स्थापित (3) सदस्य

प्रश्न:

उत्तर (e) (i) स्थापना → 1 जनवरी 2015 → शासी परिषद
(ii) अध्यक्ष → प्रधानमंत्री, भाग → विशेष सदस्य → पदेन सदस्य।
(iii) यह भारतीय थिंक टैंक है

प्रश्न:

उत्तर (f) अनुच्छेद [25-28] तक विधमान है, धर्म को [25] अबाध रूप से मानने, प्रचार-प्रसार करने, संस्था [26] स्थापना, करारोपण छूट (27) धार्मिक शिक्षा (28)

प्रश्न:

उत्तर (g) वल्लभभाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था।

प्रश्न:

उत्तर (h) अनुच्छेद 243(b) द्वारा स्थापित → ग्राम सभा यानी ग्रामवासी इसके सदस्य यह पंचायत विधायी इकाई है।

प्रश्न:

उत्तर (i) (i) आतंकवाद (ii) नक्सलवाद (iii) अलगाववाद (iv) हिंसावाद (v) साइबर हमले व आक्रमण (vi) बाह्य युद्ध (vii) बम विस्फोट आदि।

उत्तर (J) (I) 7 अध्यक्ष → राज्यपाल द्वारा नियुक्त।
(II) अन्य सदस्य → राज्यपाल द्वारा निर्धारित उन्हीं के द्वारा नियुक्त।

प्रश्न:

उत्तर (K) (I.) राजनैतिक दबाव, (II) निष्पादीकरण का अभाव (III) कार्पोरेट हस्तक्षेप व कडिंग (IV) केकुनूप की बढ़ती संख्या (V) 25x7 मॉडल।

प्रश्न:

उत्तर (L) दा वेदिंग कॉरवीजा, दा गुन हॅलिमशन ऑफ करेट, भारत ऑफ पाकिस्तान।

प्रश्न:

उत्तर (M) (I) 243(ZA) के तहत राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण संकल्प पारित करना
(II) 312(A4) नयी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन

प्रश्न:

उत्तर (N) महात्मा गांधी विचार निर्धन संबंधी लोगों के आधिपत्य कल्याण पर ध्यान दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने अपनाया।

) (i) लैंगिक (ii) आर्थिक (iii) सामाजिक
(iv) नस्लीय (v) ~~जातीय~~ | राजनैतिक |

(A)
बहुदलीय व्यवस्था से तात्पर्य एक लोकतांत्रिक राज्य में एक से अधिक राजनैतिक दलों की भागीदारी से है।

भारत ने अपने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया।
यह व्यवस्था कई मायनों में सफल सिद्ध हुई।
(i) राजनैतिक निरकुंशता पर नियंत्रण
(ii) विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, के लोगों के हितों की पूर्ति को बढ़ावा।
(iii) एक निश्चित विचारधारा का अधिकार होने पर रोक लगायी।
(iv) भिन्न-भिन्न विचारधाराओं ने आवश्यकता होने पर सफल गठबंधन किया।
परन्तु यह बहुदलीय प्रणाली (1951 - 2014) कई चुनौतियों को उत्पन्न करने का कारण बनी।

(i) (1952-67) तक एकदलीय शासन हावी रहा।
(ii) केन्द्र-राज्य भिन्न दल उपस्थिति ने विवाद को जन्म दिया।
(iii) राजनैतिक लाभ हेतु राष्ट्रीय मुद्दों का विरोध
(iv) धर्म/जाति आधारित दलों का उदय।
(v) कुछ दलों ने भाषा, क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन दिया।
(vi) (1989-92) तक अस्थिर सरकार का बड़ा कारण बहुदलीय व्यवस्था रही
(vii) दलबदल द्वारा सरकारों को हटाया जाना
(viii) चुनावों की आवृत्ति ने अपव्यय/खर्च को बढ़ाया
(ix) अनेक दलों की उपस्थिति (फर्स्ट-पास्ट द पोस्ट) प्रणाली में अल्पसंख्यक सरकार स्थापना करती है।

परन्तु भारत में अनेक दलों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर (कुछ) दल ही सक्रिय है। तथा बहुदल प्रणाली नागरिकों को अधिक विकल्प व प्रतिनिधि अवसर देती है। पिछले 12 वर्ष में भारतीय व्यवस्था अनेक कमियाँ रही है जिसे चुनाव सुधारों द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।

Nema Books -920033336

(B) संविधान संशोधन संसद द्वारा अनुच्छेद (368) के तहत किया जाता है

प्रक्रिया - (I) किसी भी सदन में प्रस्तावित।

(II) दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित हो (संघीय विषयों होने पर आधे से अधिक राज्य सामान्य सहमति)

(III) अंतः राष्ट्रपति अनुमति देने हेतु बाध्य होगा।

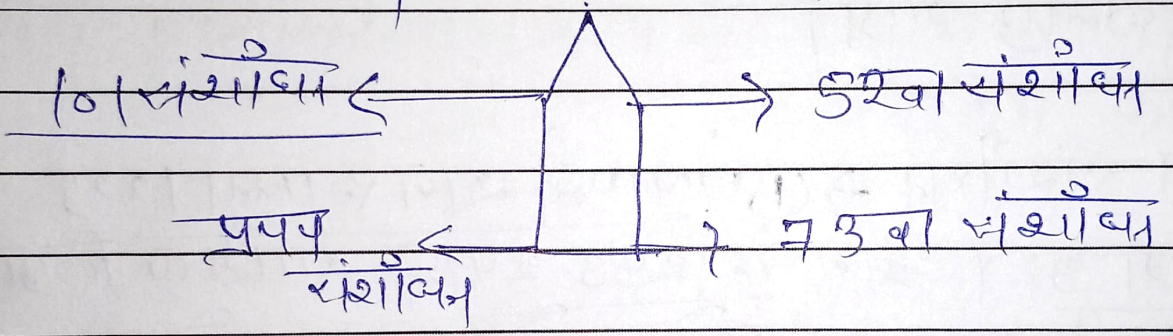

(a) प्रथम संशोधन → 1951 में कर संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गयी जिससे शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के बाहर होगा। (I.R. कोल्हावाद के बाद न्यायिक समीक्षा में शामिल) - 2007।

(b) 42वां संशोधन → 1976 में किया गया मिनी संविधान कहा गया।

Nema Books -9200333367

(i) अनुच्छेद 51(A) शामिल कर मौलिक कर्तव्य जोड़े।
(ii) अनुच्छेद 39(a), 48(a), 43(a) निदेशक तत्व जोड़े
(iii) निदेशक तत्व को अधिक प्राथमिकता, मौलिक अधि।
(iv) समवर्ती सूची में वन, वन्यजीव, शिक्षा, माप-तौल विषय शामिल किए गए।

(3) 52 वां संशोधन → 1985 में किया गया जिसके तहत (10) अनुसूची को जोड़ कर दलबदल निरोध अधिनियम बनाया गया।

(4) 73 वां संशोधन → (i) पंचायती राज स्थापना 1993 भाग 9 (अनुच्छेद 243-243O) शामिल किया
(ii) ग्यारवीं अनुसूची को जोड़कर 29 विषय पंचायत को सौंपे गए
(iv) त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत

(5) (101) संशोधन → (2016) में किया गया।
(i) GST कर व्यवस्था लागू (केन्द्र व राज्य) करों का एकीकरण
(ii) अनुच्छेद 279A → GST परिषद की स्थापना।

Nema Books -9200333367

(8) नवीन लोकप्रबंधन से तात्पर्य है निजि क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को सार्वजनिक प्रबंधन में शामिल करना। सर्वप्रथम यह शब्द क्रिस्टोफर हुड द्वारा प्रतिपादित किया गया।

इसके निम्न नवीन आयाम

(i) विनौकरशाहीकरण → लालफीताशाही, सरलाती निष्पादन कम कर। उद्यमवादी प्रबंधन पर बल।

(ii) तकनीक → पेशेवर प्रबंधन पर बल निजि क्षेत्र तकनीक को शामिलकरना उदा. लेटरल एंट्री।

(iii) राजकोषीय मितव्ययिता → सार्वजनिक व्यय अपव्यय पर नियंत्रण तथा व्यय में अनुशासन उदा. FRBM Act 2003।

(iv) विकेन्द्रीकरण → केन्द्रीकरण का विरोध तथा सत्ता विकेन्द्रीकरण व जनभागीदारी उदा. पंचायती राज।

(v) निजि भागीदारी → PPP के आधार पर सरकार निजि सहयोग।

(6) प्रबंधन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ावा (RTI, 2nd ARC)।

विकास प्रशासन → वह प्रशासन जो विकास लक्ष्यों पर केन्द्रीत।
U.L. गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित।
इसके भिन्न आयाम है

(a) परिवर्तनवादी → यथास्थिति का विरोध स्थिति अनुकूलता पर बल।
(B) लक्ष्यन्मुखी → निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्ती उपाय।
(c) नियोजनवादी → संसाधन के बेहतर प्रयोग हेतु योजना बनाना।
(d) परिणामन्मुखी → प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना।
(e) जनभागीदारी → लोगो को नीति निर्माण में शामिल करना।
कहा उचित होगा विकास प्रशासन व नवीन लोकप्रबंधन एक-दूसरे के विकास को प्रोत्साहित करते है तथा वर्तमान वैश्वीकरण, उदारीकरण इनकी महत्ती आवश्यकता।

(D) संविधान भाग (4) में अनुच्छेद (36-51) तक नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गये हैं।
इसके निम्न उद्देश्य है
→ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना।
→ राज्यो को नीति निर्माण में सहायता।
→ सरकारो को उत्तरदायी बनाना।
→ सामाजिक-आर्थिक समानता व न्याय की स्थापना।
निर्देशक तत्वों में निम्न गांधीवादी तत्व शामिल

(I) अनुच्छेद 40 (पंचायतों की स्थापना)
(II) अनुच्छेद 43 (कुटीर व लघु उद्योग को बढ़ावा)
(III) अनुच्छेद 46 → अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े (आर्थिक-शैक्षणिक) के लिए विशेष प्रावधान करना।
(IV) अनुच्छेद 47 → मद्य निषेध को लागू करना।
(V) अनुच्छेद 48 → दुधारू पशु के वध पर रोक तथा पशुनस्ल में सुधार किया जाए। तथा कृषि में नयी तकनीकें अपनायी जाए।

गांधीवादी सिद्धांतों ने निम्न प्रकार शासन को प्रभावित किया।

(i) सत्ता का विकेन्द्रीकरण के लिए प्रोत्साहित किया (73/74) संशोधन पंचायती राज व्यवस्था।

(ii) ग्रामीण विकास व लघु-कुटीर उद्योग हेतु नीति निर्माण पर बल। राष्ट्रीय खादी बोर्ड, मनरेगा, DPMRCM

(iii) मद्य निषेध, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध के लिए बाध्य बनाया। 85% पैकेट पर केशर चेतावनी।

(iv) पशुवध पर रोक (गोवध निषेध अधिनियम) व निरन्तर किए जा रहे पशु नस्लों में सुधार

(v) वंचित SC/ST वर्ग हेतु SC/ST अधिनियम। पुरस्कृत आयोग व आरक्षण व्यवस्था।

(vi) कृषि क्षेत्रों में नई तकनीकी को अपनाने पर राज्य द्वारा बल।

अतः गांधीवादी निर्देशक सिद्धांतों ने शासन को जनकेन्द्रित ग्रामकेन्द्रित व रोजगार केन्द्रित बनाने में महती भूमिका निभाई।

(E) संविधान अनुच्छेद 32 के तहत SC व (226) के तहत HC को रिट क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी की जाती है

(I) बंदी प्रत्यक्षीकरण → किसी को अनैतिक, निरपराध रूप से बंदी बनाने के विरुद्ध रूपये संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है।

(II) परमादेश → न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद कार्यरत व्यक्ति से अपने कार्य व उत्तरदायित्व पूर्ण न करने पर जारी की जाती है कार्य हेतु आदेश दिया जाता है।

(III) प्रतिषेध → "रोकना" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करने पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है।

(IV) उत्प्रेषण → अधिनस्थ द्वारा हस्तक्षेप न करने पर संबंधित याचिका को स्वयं के पास मंगवाना।

(5) अधिकारपृच्छा → किसी सार्वजनिक पद पर कार्यरत व्यक्ति से उस पद के पर उसके दावे के विरुद्ध जारी होती है।

(SC व HC) दोनों के क्षेत्राधिकार में कुछ भिन्नताएं पायी जाती है।

(a) SC केवल मौलिक अधिकार उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता (HC) अन्य विषयों पर भी।

(B) SC सभी संविधान कानूनी- विषयों के मामलों पर तथा सम्पूर्ण देश की क्षेत्राधिकार पर लागु होती है। वही (HC) रिट क्षेत्राधिकार की सीमा वह राज्य है अन्य राज्य व्यक्ति पर तब लागु होगा जब मामले से जुड़ा हो।

(C) SC रिट अधिकार मूल है वह वादी को कार्यवाही हेतु मना नहीं कर सकता HC का यह अधिकार वैकल्पिक निर्णय पर आधारित है।

अतः स्पष्ट है कि HC का रिट क्षेत्राधिकार SC से अधिक विस्तृत है।

उत्तर : (A) प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम - 2002 द्वारा प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया (2003)

संरचना → (1) अध्यक्ष व अन्य (6) सदस्य होते हैं

→ केन्द्र द्वारा नियुक्ति।

→ अध्यक्ष → पूर्व HC न्यायाधीश हो या अंतराष्ट्रीय वित्तिय अनुभवी या विधिवक्ता।

भूमिका → (1) प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों की जाँच

(ii) बाजार एकाधिकार पर नियंत्रण।

(iii) प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतोंपर रोक लगाकर पिडित की क्षतिपूर्ती करना।

(4) व्यापार प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता अधिकार को बढ़ावा देना

उत्तर :

(B) संविधान भाग (11) अनुच्छेद (268-293) तक वित्तीय संबंध स्पष्ट।

(i) कर विभाजन → संघ (12) विशेष राज्य (15) विषय समवर्ती सूची पर केन्द्र का आरोपण अधिकार।

(ii) कर दायित्व → (i) अनुच्छेद 268 → केन्द्र द्वारा आरोपित राज्य द्वारा अधिगृहित व उपयोग।

(iii) अनुच्छेद 269 → केन्द्र द्वारा आरोपण - अधिग्रहण तथा राज्यों - केन्द्र के मध्य विभाजित।

(iv) अनुच्छेद 272 → केन्द्र द्वारा ही आरोपण - अधिग्रहण अर्थात (सरचार्ज - सेस)

(v) विविध अनुदान, वित्त आयोग, आदि संबंध निर्धारित तय

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(C) निम्न उद्देश्यों के कारण नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता को स्थापित किया।

(i) शीत युद्ध से अपनी स्वायत्तता बनाए रखना (ii) वैश्विक गुटबाजी से देश की सुरक्षा (iii) शीत युद्ध में तृतीय ध्रुव का निर्माण (iv) उपनिवेशिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना (v) विश्व में शांति व समृद्धि हेतु वैश्विक शांति संतुलन (vi) दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

(vii) राष्ट्र संप्रभुता बनाए रखना। (viii) साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध

...questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

प्रश्न: (2.2)

उत्तर (D) लोक प्रशासन का भिन्न पहलु है।

(I) राजनितिक नीती निर्माण व उसके सफल क्रियान्वन मे

(II) राष्ट्र मे शांति व सुव्यवस्था बनाए रखना।

(III) वाणिज्य सेवाओ का सर्जन करना।

(IV) सामाजिक न्याय प्राप्ती व आर्थिक विकास

(V) आर्थिक असमानता को मिटाना तथा समावेशी विकास पर बल

(VI) रोजगार का सर्जन करने वाला माध्यम

(VII) सामाजिक जागरूकता व परिवर्तन का कारक।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर (E) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत आयोग 1992 मे स्थापित।

संरचना → 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य

अध्यक्षनाम → रेखा शर्मा

भूमिका → (I) संवैधानिक - वैधानिक महिला अधिकारों की सुरक्षा।

(II) महिला अधिकार उल्लघन मामलो की जाँच।

(III) केन्द्र को नीती निर्माण मे सहायता।

(IV) महिला संबंधि मामलो को न्यायालय तक पहुंचाना।

(V) पिडिता हाटलाइन, अन्य सहायता, संरक्षण कार्य

उत्तर :

(F) विकास प्रशासन से तात्पर्य है जो नियोजित तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक लक्ष्य प्राप्ति करे।

विशेषता → (I) यह लक्ष्योन्मुखी प्रशासन।

(II) यह पारदर्शिता व उत्तरदायित्व पर केन्द्रीत

(III) यह परिवर्तनशील व परिणामोन्मुखी।

(IV) यह पदसोपान को अस्वीकार करता है

(V) यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण व अधिकतम जनभागीदारी को प्रोत्साहन।

(V) यह तकनीकी को शामिल करता है

(V) व्यावहारिक करता है नीति, रणनीति, योजना, परियोजना।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर : (J) हेनरि फेयोल अनुसार सत्ता आदेश देने व कार्य करवाने की शक्ति है।

इसके निम्न प्रकार है

(I) मुख्य सत्ता → जिसके आदेश बाध्यकारी हो। उदाहरण न्यायपालिका

(II) शेषिक सत्ता → आदेश सलाहकारी उदाहरण NHRC

(III) विशिष्ट → मुख्य सत्ता का विशेष उद्देश्य पूर्ति हेतु रक्षित सत्ता में रूपान्तरण।

मैक्स वेबर ने भी तीन प्रकार बताये

(I) परम्परागत → धर्म, रीति-रिवाज → शपथ धारणा

(II) करिश्माई व्यक्तित्व → गांधी, हिटलर, मंडेला

(III) कानूनी सत्ता → संविधान या कानून से प्राप्त।

उत्तर :

(H) विभिन्न उद्देश्य पूर्ति हेतु निर्मित कोई भी गैर-लाभकारी संगठन सिविल सोसायटी माना जाता है।

सार्वजनिक आंदोलन में भागीदारी =

(i) नागरिक मांगों को उठाती है।

(ii) सार्वजनिक नीतियों का मूल्यांकन।

(iii) सरकार को उत्तरदायित्व बनाती है।

(iv) भ्रष्टाचार पर निगरानी व पारदर्शिता प्रोत्साहित

(v) सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रोत्साहन।

उदा. बचपन बचाओ, हेल्पेज, इंडिया भ्रष्टाचार सेवी (C.S) है।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर (I) 2005 अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित इनकी निम्न भूमिका।

(i) प्रशासन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ावा।

(ii) प्राधिकरणों को सूचना प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध करना।

(iii) लोगों की सूचना तक पहुंच बढ़ाना तथा सूचना न मिलने पर शिकायत निवारण एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना।

(iv) सूचना अधिकारियों का कार्य उल्लंघन पर दण्ड देकर उत्तरदायी बनाना।

SECTION -A

खंड-'अ'

प्रश्नः 2.

Question.2

निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 (छः) अंकों का है।

Write the answers of any ten of the following questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

प्रश्नः (2.2)

उत्तर :

(7) (1) विज्ञानवादी उपागम → टेलर द्वारा प्रतिपादित

विशेषता → (1) कार्य को विज्ञान के रूप

में विकसित करना (11) उचित अनुसंधान व

प्रमाणित सिद्धांतों को संगठन में अपनाना।

(111) योग्यता आधार पर लोगों का चयन करना

(4) प्रबंधक व श्रमिकों के मध्य अधिकतम समन्वय

(5) आर्थिक प्रोत्साहन पर बल → विभेदीकृत पद्धति।

(2) मानव संबंध उपागम → एल्टन मैयो।

(1) मानवीय संबंध पर बल (11) अधिकतम मानवीय

संतुष्टि पर बल (111) श्रमिक व प्रबंधक में सहयोग।

(4) अनौपचारिक संगठन को महत्व आदि।

[illegible]